have brought enough quantity of rapeseed oil and arranged for its refining and we are making it available as Rs. 750 per kg. Here again, Sir, an adequate and efficient distribution machinery is also a point and, to that extent, if there is any grievance from the hon. Member that it is not available from particular shops, I am prepared to look into it. I can assurejhis House, because this House is the representative of the various States in the country, that the Central Government is prepared to...

SHRI KALYAN ROY : Let him buy a kg. of mustard oil. I will give him Rs. 10.

MR. CHAIRMAN : You can go to . him separately and ask him.

SHRI MOHAN DHARIA : Mr. Roy, there are certain parliamentary procedures. These exhibitions may give you some publicity, but it will not serve the purpose.

SHRI KALYAN ROY : You are only protecting the traders.

SHRI MOHAN DHARIA : No, I am not protecting anybody. I told you that we have delegated adequate powers .and I am prepared to give additional powers, there is no question about that. I was only saving that so far as the refined . rapeseed oil was concerned, I would like to give an assurance through you, Sir, that whatever is the demand of the State Governments for this refined rapeseed oil, which could be sold at Rs. 7.50 per k.g., I am prepared to meet the whole of the demand. It is for the State Governments and for you friends to take this challenge to the Chief Ministers. If they are not willing, it will not be possible , for the Central Government alone to take it up.

MR. CHAIRMAN : Next Question. *{Interruptions).* Please excuse me. We have covered only three questions as I told you. *{Interruptions).* What does that matter ? Next Question.

अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सूखे मेवों का आयात

*574. **श्री नत्थी सिंह :**
श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :†
श्री भोला पासवान शास्त्री :
श्री प्रेम मनोहर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व तक अफगानिस्तान से प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपयों के सूखे मेवों का आयात होता था ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान व्यापारियों को मध्य एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों से सूखे मेवों को आयात करने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या (i) अफगानिस्तान और (ii) अन्य देशों से आयात की गई इन मदों के मूल्यों और दरों में कोई अन्तर था ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इस नीति में संशोधन करने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

Import of dry fruits from Afghanistan and Central Asia

*574- SHRI NATHI SINGH :
SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI:f SHRI BHOLA PASWAN SHASTRI: SHRI PREM MANOHAR :

Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state : .

(a) whether it is a fact that dry fruits worth Rs. 150 million were annually

(The question was actually asked on the floor of the House by Shri Nageshwar Prasad Shahi.

J[ ] English translation

imported from Afghanistan till about two years back ;

(b) whether it is a fact that during the last two years traders were permitted to import dry fruits from other countries in Central Asia and Africa ;

(c) whether there was any difference in the value and rates of these items (i) imported from Afghanistan ; and (ii) other countries; if so, what are the details thereof; and

(d) whether Government propose to revise this policy ; if not, what are the reasons therefor ?1

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गत चार वित्तीय वर्षों में अफगानिस्तान से मेवों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :

वर्ष	आयातों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1973–74	10.35
1974–75	10.82
1975–76	6.15
1976–77	10.80

मेवों का आयात परम्परागत रूप से अफगानिस्तान के अलावा ईरान से किया जाता है । 1 मार्च, 1977 से अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य देशों से मेवों का आयात निर्बाध लाइसेंस योजना के अन्तर्गत लाया गया है । अफगानिस्तान से आयात, भारत-अफगान व्यापार तथा भुगतान करार 1975 के अन्तर्गत किए जाते हैं ।

1976–77 में इन देशों से औसत एकक लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :

मद	एकक मूल्य प्रति किग्रा० (रु० में)
बादाम	
अफगानिस्तान	13.14
अन्य	20.40
पिस्ता	
अफगानिस्तान	30.06
अन्य	37.49
सूखे अंजीर	
अफगानिस्तान	10.18
अन्य	6.25
द्राक्षा	
अफगानिस्तान	7.33
अन्य	3.20
खूबानी	
अफगानिस्तान	10.28
अन्य	12.00
आलूचे तथा आलू बुखारे	
अफगानिस्तान	8.60
अन्य	उपलब्ध नहीं

मेवों की आयात की नीति पर 1978–79 की सामान्य आयात नीति के साथ विचार किया जायेगा ।

f[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

f[ ] English translation.

Statement

The value of dry fruits imported from Afghanistan during the last four financial years were as follows :

Year	Value of imports (in crores of Rs.)
1973-74	10·35
1974-75	10·82
1975-76	6.15
1976-77	10.80

Dry fruits are traditionally imported from Iran, besides Afghanistan. From 1st March, 1977, the import of dry fruits has been brought under the free licensing scheme for destinations other than Afghanistan. The imports from Afghanistan continue to deeflected under the Indo-Afghan Trade and Payments Agreement, 1975.

The average unit c.i.f. value per kg. from these countries during 1976-77 were as follows :—

Item	Unit value per kg. (in Rupees)
Almonds	
Afghanistan	13·14
Others	20·40
Pistachionuts	
Afghanistan	36·06
Others	37·49
Figs, dried	
Afghanistan	10.18
Others	6.25
Raisins	
Afghanistan	7·33
Others	3·20
Apricots	
Afghanistan	10·28
Others	12·00
Plums and prunes	
Afghanistan	8·60
Others	N.A.

The import policy for dry fruits will be considered, alongwith the general import policy for 1978-79.]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे जो शंका जाहिर की गई है उसकी ताईद होती है । अफगानिस्तान से इस देश के विशेष सम्बन्ध रहे हैं और अफगानिस्तान इस देश का हमेशा से ही बहुत ही अभिन्न मित्र साबित हुआ है । यहां तक कि पाकिस्तान के हमले के समय भी अफगानिस्तान की सहानुभूति हिन्दुस्तान के साथ रही है । अफगानिस्तान का व्यापार मुख्यत: मेवे का है जिससे अफगानिस्तान को विशेष लाभ होता है, इसीलिए यह देश अफगानिस्तान से ही मेवा मंगाता रहा है ताकि उसको कुछ लाभ होता रहे । श्रीमन्, इसमें जो विवरण है उससे साबित होता है कि अफगानिस्तान से 13.14 रु० प्रति किलो के भाव से बादाम आता है जब कि दूसरे देशों से 20.4 रुपए प्रति किलो के भाव से आता है । उसी तरह से पिस्ता भी अफगानिस्तान से सस्ता आता है और दूसरे देशों से महंगा आता है । खुबानी की भी यही हालत है । इसके बावजूद भी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा लगता है कि व्यापार विभाग के अधिकारी ऐसे व्यापारियों की साजिश से इस तरह के लाइसेंसों को प्राथमिकता देते हैं जिससे कि मेवे अफगानिस्तान से न आकर दूसरे देशों से आयें ।... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, will you stop?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये, हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती को ध्यान में रखते हुये सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि ये मेवे केवल अफगानिस्तान से ही मंगाये जायें ।

MR. CHAIRMAN: If your supplementaries are going to be so big, we will never cover anything, You can be brief, at least.

SHRI MOHAN DHARIA: I will try to be brief, Sir. We value our friendship with Afghanistan and according to our agreement. . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हिन्दी में जवाब दीजिए ।

श्री मोहन धारिया : हिन्दी में जवाब देता हूं । अफगानिस्तान के साथ हमारी जो दोस्ती है यह बड़ी महत्व की है और इस हिसाब से अफगानिस्तान के साथ जो हमारा करार हुआ है इस करार का पूरा पालन जरूर होगा ।

जो दूसरी बात हमारे मित्र ने उठाई है कि दूसरी जगह से इजाजत दी जाती है व्यापारियों को, यह सही है कि इनके दाम बहुत बढ़ गये थे, इसलिए कुछ और लाइसेंस दिए गए । लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि अफगानिस्तान को कोई तकलीफ दें, ऐसा नहीं होगा । मैं और भी फैसला कर रहा हूं कि पहले हमारे मुल्क में जो ऐस्टेब्लिश्ड इम्पोर्टर्स थे उनका भी

They had nearly monopolised the whole of the trade. Now I am considering to do away with this system of established importers.

अगले साल के लिए जो नीति तैयार हो रही है, उसमें यह फैसला जरूर किया जाएगा । हम यह उम्मीद करते हैं कि एक तरफ तो हमने जो करार किया हुआ है उसका पालन होगा और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के लोगों को ठीक दाम पर चीजें मिल सकें इसको ख्याल में रखकर हम काम करेंगे ।

MR. CHAIRMAN: Straightway put your second supplementary question.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपने अब जो नई नीति तय की है उसके अन्तर्गत हमारे देश में मेवा कम आ रहा है, इसलिए वह महंगा बिक रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के लोगों को सूखा मेवा सस्ते दाम पर मिले, इस पर गौर करके क्या आप अपनी नीति को बदल कर कोई इन्तजाम करने की कोशिश करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : मैंने सदन में जो उत्तर दिया है उसमें यह बताया है कि इन चीजों के दाम क्या हैं और कितने बढ़े हैं । ये चीजें फ्री लाइसेंस के अन्तर्गत ओपन मार्किट में दी जाती हैं । व्यापारियों को जहां से सस्ती चीजें मिलती हैं वहां से वे उनको मंगाते हैं . . .

(Interruptions)

SHRI KALI MUKHERJEE: These are luxury items. These are not necessary for the general public. We are wasting the time of the House.

श्री प्रेम मनोहर : आपने अपने विवरण में बताया है कि अफगानिस्तान में जो बादाम मंगाये जाते हैं उनका दाम 13.14 रु० प्रति किलो होता है जब कि हिन्दुस्तान के बाजारों में यह 64 रु० या इससे भी अधिक दाम पर बिकता है । इसी प्रकार से पिस्ता 36.06 रु० प्रति किलो के हिसाब से मंगाया जाता है और बाजार में 120 रु० प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है । व्यापारी लोग थोड़ी सी शौर्टेज को अधिक बताकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं । ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी 10 करोड़ रुपयों की वस्तुओं का जो वे आयात करते हैं क्या उसमें दो तीन करोड़ की और वृद्धि करने की कृपा करेंगे जिससे बाजार में लोगों को ड्राइ फ्रूट सस्ते दामों पर मिल सकें और हमारे देश का व्यापारी वर्ग इस क्षेत्र में जो दुगुना चौगुना फायदा उठा रहा है वह इतना फायदा न उठा सके । इस सम्बन्ध में क्या आप कोई नई पालिसी अपनाने का प्रयत्न करेंगे ?

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, so far as the prices are concerned, by and large there is 120 per cent import duty. Secondly, I can very well appreciate that this limit of Rs. 10 crores should be enhanced, but let us not forget that we cannot fritter away our foreign exchange also. We have to maintain a balance detween how we spend our foreign exchange and at the same time to what extent it should be made available. What we are trying to do is...

SHRI PREM MANOHAR: But the consumers should not be exploited by the traders.

SHRI MOHAN DHARIA: Perfectly understood. It is in this context that we have decided to give more and more role to our consumer societies so lhat the consumers are not exploited.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने इन चीजों के जो भाव बताये हैं, क्या यह सही है कि उससे चौगुनी कीमत पर बाजार में ये चीजें बिकती हैं ? अगर यह बात सही है तो आप इस पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं । बाजार में बादाम के दाम 70–75 रु० प्रति किलो हैं जब कि मंत्री महोदय ने इसके दाम 13/14 रु० बताये हैं । कम से कम आप इसको 50 रु० तक तो ला ही सकते हैं ।

श्री मोहन धारिया : यह ऐसी चीज नहीं है कि इन चीजों पर कंट्रोल करके राशनकार्ड पर दिया जाय । यह नहीं हो सकता है । व्यापारी ज्यादा मुनाफा न लें, हमारे जो कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका फायदा उठाकर ये चीजें लोगों को सस्ते दाम पर और रिजनेबल भाव पर मिल सकें, इस हद तक विचार करने के लिए हम तैयार हैं ।

SHRI SUJAN SINGH: These are luxury items. Can these not be banned altogether?

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, this decision was taken for one more reason—that is, there was a lot of smuggling. Take for instance the cloves. The prices had gone up to Rs. 1500 per kilogram and it is because of our decision that they have come down to Rs. 300 - 400 per kilogram. We want to stop that smuggling. Therefore, it cannot be banned altogether.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: The Minister Incharge of Commerce and Civil Supplies and his colleagues are very anxious to see that the prices of articles consumed by the public comes to proper levels. Keeping in view this aspect and the high prices prevailing at present of the dry fruits and spices, I would like to know whether the Government is thinking in terms of liberalising the import policy on dry fruits and allowing larger imports, in the context of the comfortable foreign exchange reserves position, from all the countries, including Afghanistan, from where these articles can be available.

SHRI MOHAN DHARIA: I have already said that so far as Afghanistan is concerned, we shall see that the Agreement is fully honoured. This House may be aware that we are having a Rupee Trade Agreement with Afghanistan, and to the extent we import there are certain export obligations also. But we shall fully honour that Agreement,

Sir, so far as full liberalisation is concerned, this House will bear with me that this foreign exchange position should be used for the industrial and economic development of the country and not for such purposes whereby this exchange position could be frittered away.